रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3520] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940
No. 3520] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

का.आ. 4334(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में उद्योग में की सेवाएं किसी तेल क्षेत्र में की सेवा जो उक्त अधिनियम, की पहली अनुसूची की मद 17 में आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसी लोक उपयोगी सेवा होगी जिसे भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1026(अ) तारीख 9 मार्च, 2018 द्वारा 16 मार्च, 2018 से छह मास की अवधि के लिए अधिसूचित की गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त औद्योगिक का लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति का छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 16 सितम्बर, 2018 से छह मास की और अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2018-आई.आर.(पी.एल.)]
कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

S.O. 4334(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services in industry **'Service in any oilfield'** which is covered by item **17** of the First Schedule to the said Act to be a **public utility service** for the purposes of the said Act, as was notified for a period of six months with effect from 16th March, 2018 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1026(E), dated the 9th March, 2018;

And whereas, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, **for a further period of six months with effect from the 16th September, 2018.**

[F. No. S-11017/ 1 / 2018 – IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.13 11:35:58 +05'30'